SHRI CHATURANAN MISHRA: I have not said that I will not ask. I said that I will convey the feelings and whatever reply I receive I will forward the same to you. That is the point. About inspection and all these things, it is not my job and I am not doing it. The inspection part is looked into by some other agency and you are aware of it. But your feelings will be conveyed and whatever report I receive, I will forward the same to you. I have said this time and again.

SHRI SURESH A. KESWANI: Sir, the hon. Minister would perhaps recollect that precisely because of the complaints of diversion of these funds there was a Committee constituted by the Central Government under the Chairmanship of the Secretary, Mr. Padmanabiah, and there were thirteen experts appointed. They had gone into it, they had investigated and they had submitted a detailed report. They have also provided guidelines as to what needs to be done and how the State Government needs to be monitored. I would request the Minister to kindly respond to this.

SHRI CHATURANAN MISHRA: We have time and again been advising the State Governments to use those funds which we give them. But then, we cannot take any action against them.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: कमेटी कांस्ट्यूट हुई थी?

श्री चतुरानन मिश्र: कमेटी तो कांस्टीट्यूट होती और हर जगह जांच करते हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: इसमें हुई थी?

श्री चतुरानन मिश्र: इसमें नहीं, इस में हमारे पास कोई खबर नहीं है।

I have told the different States.

अगर स्टेट्स खर्चा नहीं करती हैं तो उन के नोटिस में हम यह लाते हैं और हम कल भी लाए हैं। लेकिन आप कहें कि एक्शन लीजिए ...(व्यवधान)... जो बात माननीय सदस्य चव्हाण साहब ने कही है, उस से तो हमने सहमति प्रकट की है कि हम आप को पूछकर अवगत करा देंगे।

Creation of Additional Posts in the Railways

*3. SHRI GURUDAS DASGUPTA:†
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government have issued instructions to create 3000 additional posts in the Railways; and

(b) if so, the zone-wise position of these additional posts created and steps being taken to fill them up?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the point is, on additional posts being created or whether they have been created or whether there is a need for them or whether the Government would like to take that problem into account, the answer does not go into the question at all. Sir, my first supplementary is, is the Government aware or is the Minister aware that there is a long standing demand for increase of manpower or induction of additional manpower in the Railways for running the trains safely? If so, would the Government consider that and would there be a ban on further recruitment in the Railways?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति महोदय, यह तो सरकार की नीति है कि हर क्षेत्र में कम-से-कम एक्सपैंडीचर किया जाए और उस दृष्टिकोण से रेलवे में भी इस नीति को लागू किया गया है। अब यह लागू किया गया है तो इस रूप में नहीं कि हम रिट्रेंच करते हैं बल्कि कोई रास्ता निकाला गया कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं, उस के अनुपात में अपाइंटमेंट किए जाएं तो कम किए जाएं। एक समय में रेलवे में 59 लाख कर्मचारी थे और आज 16 लाख कर्मचारी बचे हैं। तो भारत सरकार की जो नीति बनती है, उस नीति को रेलवे भी फालो करने का काम करती है। अब जहां तक सवाल है आवश्यकता के मुताबिक, तो आवश्यकता के मुताबिक हम पदों का सृजन करते हैं, लेकिन उस के लिए "मैचिंग सरेंडर" का सिद्धांत अपनाया गया है कि जितनी पोस्ट्स कम क्रिएट करते हैं, उसी के अनुपात में दूसरे पैसे को सरेंडर करना पड़ता है।

अब माननीय सदस्य ने जो 3 हजार कर्मचारियों के संबंध में प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं कि इन का आशय शायद सफाई मजदूरों से है क्योंकि सफाई मजदूरों के संबंध में मामला आया था और हम ने इसी सदन में घोषणा की थी कि सफाई मजदूर का काम हम कांट्रेक्ट सिस्टम से नहीं कराएंगे और उस की भर्ती रेलवे के द्वारा करवाएंगे। उस दृष्टिकोण से यह बात सही है कि रेलवे

†The Question was actually asked in the floor of the House by Shri Gurudas Dasgupta.

बोर्ड की तरफ से विभिन्न जनरल मैनेजरों को आदेश जारी किए गए हैं कि जो सफाई मजदूर का काम है और जो कांट्रेक्ट सिस्टम के ऊपर है, उस को 31 के बाद खत्म किया जाए। उस की बहाली रेलवे द्वारा कराई जाए। अब इस संबंध में जहां तक पैसे का सवाल है, तो जितना पैसा कांट्रेक्ट सिस्टम में लगता था, उतना ही पैसा रेलवे के द्वारा बहाल करने में हुआ है और यह पूरी-की-पूरी संख्या 3 हजार की संख्या के करीब हो जाती है। इसलिए उस दृष्टिकोण से हम ने उस को किया है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I don't really understand the answer.

MR. CHAIRMAN: Why did you not understand the answer?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I will put my second supplementary later. The issue now is that the Minister has come to the point that there were 3,000 safai karamacharis who were working on contract basis. Will the Minister tell us whether they are going to be absorbed or they have already been absorbed? There is no question of principles. Before I come to the second supplementary, the Minister must clarify whether they have been absorbed or the likely to be absorbed. What is the Government's policy on this question?

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, the posts are already sanctioned.

अभी जैसे सदर्न ईस्टर्न रेलवे का है, सदन ईस्टर्न रेलवे में 132 की बहाली वहां हो चुकी है, नार्दर्न रेलवे में 55 लोगों की बहाली हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि बहाली, उसको रखने की प्रक्रिया जारी है, कांट्रेक्ट सिस्टम को खतम कर दिया गया है। अभी 8 तारीख को हमने साफ तौर से आदेश जारी किए, आदेश जारी करके हम स्वयं उसकी मोनेटरिंग कर रहे है। एक महीने, डेढ़ महीने के अंदर सारे के सारे बहाल हो जाएंगे।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, my second supplementary is that it is necessary to fill up some of the vacancies so as to run the trains safely. As I understand from the Minister, because of shortage of funds, they are not filling up the vacancies and posts in the Railways are being abolished at ransom. According to my calculations, in one of the Railways, 35 posts are vacant and these posts are being abolished gradually. I understand the resource crunch and the fund problem. But the question of safety cannot be compromised. Therefore I would like to know from the hon. Minister whether he is aware that because of serious shortage of trained personnel in different branches of the Railways, safety has become a casualty. In view of the fact that safety is becoming a casualty and there have been a number of accidents, will the hon. Minister consider again the question of appointment or induction of additional manpower at least to create a situation where safety does not get compromised? This is important because there have been a number of accidents and people without experience are being employed for laying of tracks, maintenance of tracks and for many other works. I, therefore, want an assurance from the hon. Minister that the question of safety will not be compromised. In order to create a safety-friendly environment, will he consider appointment or induction of additional manpower?

SHRI RAM VILAS PASWAN: In any case, safety will not be compromised.

जहां तक सवाल है मेनपावर के कारण, आदमी की संख्या के कारण या एम्पलाईज की संख्या के कारण हमारी सेफ्टी के ऊपर खतरा है या एफिसिएन्सी के ऊपर खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको जब जब जिस पोस्ट की आवश्यकता होती है, हम उसको करते हैं और जहां हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर काम चला सकते हैं ....(व्यवधान)....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Then, will the Minister agree with me? There are a lot of reports on lack of safety in trains. There are enquiry Committee reports which indicate that due to lack of sufficient manpower, safety has become a casualty.

SHRI RAM VILAS PASWAN: If that is so, then it is wrong.

सेफ्टी का जहां तक मामला है, तो एक्सीडेंट के कई कारण हैं। एक्सीडेंट के कारण में हमारा ट्रेक का कारण आता है, एक्सीडेंट के कारण में और बहुत सारी चीजें आती है। जहां तक मैनपावर का सवाल है, आदमी का मामला है, वह अभी तक जितना हमने रिव्यू किया है, उसमें सेफ्टी के ऊपर डेन्जर आदमी के कारण, एम्पलाईज के कारण है, ऐसी बातें नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Giri Prasad not present. Shrimati Veena Verma.

श्रीमती वीणा वर्मा: सर, मै माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि अभी हाल में जो 6 नए रेलवे जोन बने है।, क्या उनके लिए आपने कोई अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की है? यदि की है, तो कितने पद दिए गए है? "बी" पार्ट, राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए बहुत से पद जो दिए जाते है, सृजित किए जाते है, वे निम्न स्तर के होते है।, जो अन्य पदों के बराबर के नहीं है। अभी हाल में "ग" क्षेत्र में जो है दक्षिण रेलवे के लिए, मद्रास दक्षिण रेलवे, सिकंदराबाद पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता, एन॰ई॰एफ॰ए॰ और गोहाटी के लिए क्या नए पांच पद उपसचिव स्तर के सृजित किए गए है? यदि हां, तो अन्य जो मध्य रेलवे, बम्बई, पश्चिम रेलवे, मुम्बई, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, इसके भी पद सृजित किए जाएंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम विलास पासवान: सर, जहां तक नए ज़ोन का सवाल है, हम लोगों ने विभिन्न रेलवे से ऑप्शन मांगा है और उसमें हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे है।

जहां तक ऑफिशियल लैंग्वेज का सवाल है, माननीय सदस्या ने इस बात को हमारी नॉलेज में लाया है, मैं स्वयं इस बात को देख लूंगा और यदि उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी पद की आवश्यकता है या पद के सृजन की आवश्यकता है तो उसके लिए हमको कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री या कोई भी, हम भी उस कमेटी में रहे हैं। उसमें कोई बाधक ज्यादा नहीं होता है और हम उसको पूरा करेंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा: क्या यह सही है कि दक्षिण रेलवे के लिए भी बोर्ड ने 5 पद ....(**व्यवधान**).....

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, this question relates to different topics. The hon. Member is asking about officers and staff relating to official language.

तो वह हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐश्योरेंस देता हूं कि यदि ऑफिशियल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा के अनुपालन के लिए पद की आवश्यकता होगी या उसका सृजन करने की आवश्यकता होगी, तो वह हम करेंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा: शुक्रिया।

SHRI R. MARGABANDU: Hon. Chairman, Sir, I would like to know whether the reservation policy is being followed in case of appointments in the Railways. I am given to understand that some instructions have been given by the Central Government that for filling up the backlog of vacancies, interview calls should be sent only to a particular section of people. I would like to know whether the Central Government is following the reservation policy in the case of appointments in the Railways.

श्री राम विलास पासवान: जहां तक रिज़र्वेशन पॉलिसी का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि रेलवे में जितने अच्छे तरीके से इसका पालन किया जाता है, वह किसी से कम है। रेलवे एक ऐसी मिनिस्ट्री है, जहां रिज़र्वेशन पॉलिसी को हम बहुत ही कड़ाई से लागू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने जितने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए हैं, उनमें पहली बार पांच-छः चेयरमैन शैडयूल्ड कॉस्ट के बनाए गए हैं और हमने कर दिया है कि 9 मैम्बर्स में से 3 शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स के रहेंगे, 3 बैकवर्ड कम्युनिटी के रहेंगे और 3 माइनॉरिटीज़ के रहेंगे।

This is applicable in the whole of the nineteen railway Recuritment Boards.

इसलिए जहां तक रिज़र्वेशन पॉलिसी का सवाल है, हम उसको बहुत ही कड़ाई से लागू कर रहे हैं। जून को हम मंत्री बने थे और 30 जून से हमने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कर दिया और हमने आफिसर्स से कहा है कि वे रिज़र्वेशन पॉलिसी को कड़ाई से लागू करें और जो अफसर इसको लागू नहीं करेगा, उसको दंडित किया जाएगा।

SHRI S.M. KRISHNA: Keeping in view both safety and efficiency, in that order, has the Railways made an internal exercise in rationalising the staffing pattern in the Railways? I am of the opinion that in certain areas there has been over staffing and in certain areas there is understaffing. So, I would like to know from the hon. Minister if an exercise has been made. If it has not been undertaken, then I would suggest to the Government that an exercise should be made in this regard before it goes in for further recruitment.

SHRI SATPAL MAHARAJ: Would you please repeat the question you have asked?

SHRI S.M. KRISHNA: Keeping in view both safety and efficiency in that order, has an internal exercise been done by the Railways about rationalising the staffing pattern in the Railways? I am given to understand that in certain areas, there has been overstaffing and in certain other areas there has been

understaffing. So, in view of this, does the Railways propose to have some indepth analysis about the staffing pattern itself before it goes in for massive recruitment in the Railways?

श्री राम विलास पासवान: निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाएगा और अभी सेफ्टी के ऊपर हमारा सेमिनार चल रहा है — कल से शुरू हुआ है, आज तक वह सेमिनार चलेगा और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसके ऊपर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

Construction of underpass near Ultadanga Railway Station

*4. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it has been decided by the Railways to construct an underpass near the Ultadanga Railway Station in West Bengal;

(b) whether it is a fact that land and part of the State Govt.'s financial contribution has been made available to the Railways;

(c) whether it is also a fact that several dated were indicated by Eastern Railway to start construction of the project; and

(d) if so, the reason for not starting the project so far and the firm schedule for the implementation of the project?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। निक्षेप शर्तों पर।

(ख) अपेक्षित भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। बहरहाल 3.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कार्य के स्थल पर 3 मीटर व्यास के सीवर पाइप के संरेखण से संबंधित ब्यौरे और इसके जंक्शन अप्रैल, 96 तक भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। राज्य सरकार द्वारा पाइप लाइन के तकनीकी ब्यौरे उपलब्ध कराने के बाद दिसंबर 1996 में टेंडर दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने तथा कार्य की शेष लागत जमा कराने के बाद ही परियोजना के कार्यान्वयन की निश्चित समयवधि निर्धारित की जा सकेगी।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, I am sorry to say the kind of statement that has been laid by the Minister on the Table of the House is a demonstration of how there can be misleading and how a total untruth can come to the House, and when I state the facts, it will be clear that the privilege of the House is also encroached upon.

As per the facts given in the statement, the project which was decided, in principle, in 1992—this project was decided in 1992—has not yet started. The zero date has not yet started. What is the sequence of events? In the closing part of (d) of the statement the Minister says, "The schedule for implementation of the project can be fixed only after the required land is made available and the balance cost of work is deposited by the State Government." Part (a) of my supplementary is whether it is a fact or not that all encroachments and all problems related to land for construction were cleared in November itself and the foundation stone-laying ceremony was held on 30.11.1995. As far as the balance money is concerned, though the tender itself was issued on 1st of May, 1995, one crore of rupees had been given by the CMDA, the State agency which is involved there, on 1st of June, 1994. So, clearly year before the tender had even been floated, the State Government had deposited the money and it said that there is no problem of money. As soon as they inform that money is required, the State Government can given money within seven days. There are several hon. Members here who had been Ministers of the Government of India, the Prime Minister is also here....

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, this is very vital. When the Central Government gives money for a Centrally-sponsored scheme, it asks for a utilisation certificate from the State Government. Without that utilisation certificate, the rest of the money does not go. But, here is a project for which the State Government had given part of the money in 1994 and the work has not yet started. It took one year just to float the tender. Then they are saying that work cannot start before the balance